भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 6138

बुधवार, 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर देने के लिए

विभिन्न क्षेत्रों में 'नाविक' संचालित उपकरणों का उपयोग

6138. श्री एम. के. राघवन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परिवहन, लॉजिस्टिक्स, मत्स्यपालन, आपदा प्रबंधन और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 'नाविक' संचालित उपकरणों के उपयोग को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में बेचे जाने वाले सभी स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में 'नाविक' प्रणाली का आमेलन अनिवार्य करने का विचार है और यदि हाँ, तो इसके पूर्ण कार्यान्वयन हेतु निर्धारण समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार सिविलियन नेविगेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए डुअल-फ्रीक्वेंसी (एल1/एल5) 'नाविक' सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है, ताकि इसकी वैश्विक प्रणालियों जैसे जीपीएस के समतुल्य सटीकता सुनिश्चित हो सके और यदि हाँ, तो इसमें अब तक प्रगति क्या रही है;

(घ) क्या घरेलू निर्माताओं को 'नाविक' चिपसेट, रिसीवर और मॉड्यूल विकसित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता या प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने 'नाविक' प्रणाली की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति और अन्य वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) के साथ इसका अंतर्नियोजन सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

****

(क) जी हाँ। सरकार ने परिवहन, लॉजिस्टिक्स, मत्स्यपालन, आपदा प्रबंधन और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 'नाविक' संचालित उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं।

..2/-

1. वास्तविक समय में ट्रेन की ट्रैकिंग: 10,400 से अधिक ट्रेनें नाविक समर्थित ट्रैकिंग उपकरणों से सुसज्जित हैं।
2. मछली पकड़ने वाले जहाजों की ट्रैकिंग: 41,000 से अधिक जहाज नाविक समर्थित ट्रांसपोंडरों से सुसज्जित हैं।
3. सार्वजनिक और वाणिज्यिक वाहनों की ट्रैकिंग: 140 से अधिक उपकरण मॉडल प्रमाणित हैं और 15 लाख से अधिक वाहनों में लगाए गए हैं।
4. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जीवन सुरक्षा संबंधी चेतावनी संदेश प्रदान करने के लिए भी नाविक का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) सरकार ने अभी तक 'नाविक' को अनिवार्य नहीं किया है। इस संभावना पर चर्चा जारी है।

(ग) जी हां। सरकार सिविलियन नेविगेशन की सटीकता में सुधार के लिए डुअल-फ्रीक्वेंसी (एल1/एल5) 'नाविक' सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है। एनवीएस उपग्रहों की श्रृंखला, जिसकी शुरुआत मई 2023 में प्रमोचित एनवीएस-01 से हुई, पारंपरिक एल5 और एस संकेतों के साथ-साथ एल1 संकेत भी प्रसारित करेगी।

(घ) सरकार ने पायलट परियोजनाओं, भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, तकनीकी सहायता, परीक्षण सहायता, उपयोग कार्यक्रमों आदि से संबंधित गतिविधियाँ शुरू की हैं। अंतरिक्ष विभाग ने राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय उद्योग मानकों में 'नाविक' को शामिल करने के प्रयास किए हैं, जिससे उत्पादों और समाधानों में 'नाविक' को कुशलतापूर्वक, सुसंगत और निर्बाध रूप से अपनाया जा सके। इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने भारतीय उद्योग द्वारा 'नाविक' चिपसेट के डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति में सहयोग प्रदान किया है।

(ङ) जी हाँ। सरकार नियमित रूप से अन्य वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) के साथ संवाद और समन्वय करती है ताकि 'नाविक' संकेतों की अन्य संकेतों के साथ अनुकूलता और अंतर्नियोजन सुनिश्चित की जा सके। यह समन्वय कार्य बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्तरों पर किया जाता है।

****